भाजपा सरकार अन्नदाता विरोधी

इन्द्री (जेके शर्मा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीष्म मेहता ने कहा है कि भाजपा सरकार अन्नदाता विरोधी है। सरकार ने किसानों को बर्बाद करने की योजना बना ली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान अन्नदाता है और आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे अन्नदाता के साथ कांग्रेस खड़ी है। अपनी सरकार आने पर तीनों अध्यादेशों को कांग्रेस रद्द कर देगी। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।

किसानों को आर्थिक व दूसरी मदद देने का ऐलान

इन्द्री (जे.के.शर्मा) किसानों पर केंद्र व राज्य सरकार के दमनचक्र के विरोध में ऑल हरियाणा पॉवर कॉरपोरेशन वर्कस यूनियन ने समर्थन कर बुधवार को दो घंटे सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आंदोलनरत किसानों को आर्थिक व दूसरी मदद देने का ऐलान भी किया।

इस मौके पर गन्ना एक्शन कमेटी के अध्यक्ष एवं भाकियू नेता रामपाल चहल ने कर्मचारियों के बीच जाकर उनके समर्थन के लिए कर्मचारियों का आभार जताया।

इस मौके पर यूनियन के नेता मलकीत सिंह, नरेश कुमार और शंटी काम्बोज ने कहा कि किसानों पर बनाये जा रहे फ़र्ज़ी मुक़दमों को अगर वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारी किसानों के समर्थन में बड़ा और लंबा आंदोलन छेड़ेंगे।

किसान पहले से ही मंदी झेल रहे हैं : बलबीर बाल्मीकि

करनाल, (जेके शर्मा) : इसराणा के विधायक बलबीर वाल्मीकि ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन अध्यादेश लाकर किसानों को परेशान किया है। किसान पहले ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे थे, लेकिन अब फिर केंद्र की भाजपा सरकार नए-नए फरमान लागू कर किसानों के साथ-साथ व्यापारियों को भी परेशान करने का काम कर रही है।

विधायक बलबीर वाल्मीकि गांव बराना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले वो युवक कांग्रेस के ब्लाकाध्यक्ष अमित बराना के निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

बलबीर वाल्मीकि ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, लेकिन सरकार इन्हें मान नही रही है। इस अवसर पर अमित बराना, राजीव बुटाना, जस्सी सिद्धपुर समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे।

करनाल में अब रोजाना 20 कुत्तों की होगी नसबंदी !

करनाल (जेके शर्मा) शहर में कुत्तों का बचना अब मुश्किल है। नगर निगम करनाल अभी तक 450 कुत्तों की नसबंदी कर चुका है। यह कार्रवाई निगम कमिश्नर विक्रम के निर्देश पर की जा रही है। शहर के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से राहत महसूस कर रहे हैं। संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह ने बताया कि अक्तूबर मध्य से यह अभियान शुरू हुआ था। जिन गली-मोहल्लों से कुत्तों को टीम पकड़कर लाती है, नसबंदी के बाद उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। अब इस काम को बढ़ाया जाएगा, रोजाना कम से कम 20 कुत्तों की नसबंदी अवश्य की जाएगी, ताकि शहर के सभी कुत्तों की नसबंदी करवाई जा सके।

निरीक्षण की जानकारी देते संयुक्त निगमायुक्त ने बताया कि नसबंदी सेंटर में जितने कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है, उसके लिए एक रजिस्टर रखा गया है, जिसका रिकॉर्ड चेक किया गया। बातचीत के दौरान इस काम को करने वाले टीम से उनकी दिक्कतें भी पूछी गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोग गली-मोहल्लो में भौंकने वाले कुत्तों को अपना कहकर उसे उठाने के लिए मना कर देते हैं, जो गलत है। लोगों के इस तरह मना करने से इस काम को शत प्रतिशत रूप से सफल नहीं बनाया जा सकेगा। अगर सभी कुत्तो की नसबंदी सफल होगी, तो भविष्य में इनके आतंक से बचा जा सकेगा।

मौके पर मौजूद नसबंदी केन्द्र के मैनेजर कंवरजीत सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते जिस शेल्टर के नीचे कुत्तो को रखा जा रहा है, उसमें रूम हीटर रखे जाएंगे, ताकि तापमान ठीक बना रहे। कुत्तों की खुराक और नसबंदी का कार्य पहले की तरह बदस्तूर चल रहा है।

परिवार पहचान पत्र के लिए 54 सेंटर

करनाल, (म.मो.) परिवार पहचान पत्र अनिवार्य बनवाने के लिए करनाल नगर निगम ने शहर की भिन्न-भिन्न 54 लोकेशन पर परिवार की डिटेल अपलोड करने के सेंटर बनाए गए हैं, जो अधिकांश कॉमन सर्विस सेंटर में हैं। निगमायुक्त ने बताया कि भविष्य में हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीमे हैं, जिनका लाभ नागरिको को दिया जाता है, लेकिन स्कीमों का लाभ लेना सुनिश्चित बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। जो सेंटर बनाए गए हैं, उनकी जानकारी इलाके के नगर पार्षद से ली जा सकती है। निगमायुक्त ने बताया कि परिवार का मुखिया अपने सभी सदस्यों के आधार नम्बर, आयु प्रमाण या वोटर पहचान पत्र तथा सम्बंधित बैंक का खाता नम्बर लेकर सेंटर पर जा सकता है।

करनाल नगर निगम को पता ही नहीं कितनी बिल्डिंगें बन रहीं!

निगम के बेईमान अफसरों का सच आरटीआई के जरिए सामने आया

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

करनाल: नगर निगम करनाल के पास यह जानकारी नहीं है कि शहर में कितने घरेलू और कितने व्यावसायिक भवन निर्माणाधीन हैं। यानी इसका मतलब है कि करनाल में जितने भी निर्माण वैध या अवैध हो रहे हैं, उसकी जानकारी निगम के पास नहीं है। यह खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई से पता चला है कि करनाल नगर निगम के अधिकारी किस तरह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर शहर में अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहा है। सीएम सिटी कहलाने के बावजूद करनाल नगर निगम के बेईमान अफसरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

करनाल के रहने वाले नरेंद्र सूखन एडवोकेट ने एक आरटीआई के जरिए करनाल नगर निगम से पूछा था कि शहर में कितने घरेलू और व्यावसायिक भवन निर्माणाधीन हैं। इनमें से जो अवैध हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नरेंद्र सूखन एडवोकेट ने यह भी पूछा था कि कितने भवन मालिकों ने अपनी बिल्डिंगों का साइट प्लान (नक्शा) करनाल नगर निगम से मंजूर कराया और कितनों ने साइट प्लान मंजूर नहीं कराया।

नरेंद्र सूखन की इस आरटीआई पर नगर निगम को सांप सूंघ गया। उसने जवाब में लिखा कि करनाल नगर निगम ने इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया है कि शहर में कितने घरेलू और व्यावसायिक भवन बन रहे हैं।

नगर निगम ने उनसे कहा कि आपने यह तो लिखा ही नहीं कि आपको यह जानकारी कब तक की चाहिए। हालांकि नगर निगम चाहता तो वह एक साल या दो साल की जानकारी दे सकता था। लेकिन उसने दूसरा बेवकूफी वाला जवाब साइट प्लान की मंजूरी को लेकर दिया। उसने लिखा है कि पिछले दो साल में 252 साइट प्लान पर प्रक्रिया की गई। लेकिन यह पता नहीं है कि इनमें से कितने मंजूर किए गए और कितने नामंजूर किए गए।

नगर निगम करनाल के दोनों जवाबों से साफ है कि वह अवैध निर्माणों के बारे में जानकारी या तो छिपाना चाहता है या फिर देना नहीं चाहता है। जिस नगर निगम को यह न मालूम हो कि कितने साइट प्लान नामंजूर किए गए या कितने मंजूर किए गए, वह शहर को किस प्रकार चला रहा होगा, उसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

थैलेसिमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप

करनाल : कोरोना महामारी के चलते पंकज गाबा के नेतृत्व में थैलेसिमिया से पीड़ित बच्चों के लिए 38वां ब्लड डोनेशन कैंप सिविल अस्पताल में लगाया गया। इस अवसर पर पंकज गाबा ने कहा कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता आई है और धीरे-धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं। गाबा ने कहा मैं उन सभी संस्थाओं का आभारी हूं जो ऐसी संकट की घड़ी में जरूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा आप के द्वारा किया गया रक्तदान किसी मां के बच्चे को बचा सकता है। इस मौके पर डॉ संजय वर्मा ने रक्तदान का महत्व बताया और कहा कि रक्तदान करने से आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और इससे इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत होता है।

करनाल में लोक अदालत 12 को

करनाल, (म.मो.): मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल अमित शर्मा ने बताया कि आगामी 12 दिसम्बर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल जगदीप जैन के मार्गदर्शन में सेशन डिवीजन, करनाल में नैशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत का आयोजन सभी प्रकार के माध्यमों जैसे व्हाट्सऐप, वीडियो कांफ्रेंसिंग और अन्य माध्यमों या निजी रूप से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करके किया जाएगा।

भवन निर्माण स्थल पर धूल उड़ी तो खैर नहीं

करनाल, (म.मो.) : शहर में जिला प्रशासन और नगर निगम भले ही हर तरह के प्रदूषण पर रोक न लगा सके लेकिन उसकी नजर अब भवन निर्माण करने वालों पर रहेगी। अगर भवन निर्माण के दौरान धूल उड़ती पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईआईए) से जुड़ी जिला निगरानी टीम हर महीने निर्माण स्थलों पर जाकर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर पहले नोटिस और फिर केस बनाया जाएगा।

प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली निर्माण कंपनियों व प्रतिष्ठानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एनजीटी की ओर से सख्त हिदायतें जारी हैं। धूल, मिट्टी या डस्ट का उचित प्रबंधन भी उनमें से एक है। ऐसी कमियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीम ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण करेगी।

उपायुक्त ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाएगा, उचित जवाब न मिलने पर केस बनाया जाएगा, जिसकी सुनवाई कुरूक्षेत्र स्थित स्पेशल एन्वायरमेंट कोर्ट में होगी। दोषी पाए जाने पर 6 साल की कैद व 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अंसल पर कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी अभियंता शैलेन्द्र अरोड़ा ने मीटिंग में बताया कि अंसल के दो प्रोजेक्ट का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया था, जिसमें निर्माण को शुरू करने की अनुमति नहीं ली गई थी। मामला इस साल का है।

संबंधित कंपनी को नोटिस दिया जा चुका है और अब उसके विरूद्ध केस तैयार किया जा रहा है जो स्पेशल एन्वायरमेंट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।

मंत्री कमलेश ढांडा के खिलाफ प्रदर्शन, मांगा इस्तीफा

करनाल, (जेके शर्मा) : आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने महिला एवं बाल विकास परियोजना मंत्री कमलेश ढांडा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्ण पार्क में सभा करने के बाद प्रदर्शन करती हुई आंगनवाड़ी वर्कर कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की गई। अध्यक्षता जिला प्रधान रूपा राणा ने की।

इस मौके पर सीटू जिला सचिव जगपाल राणा, ओपी माटा, रूपा राणा, बिजनेश राणा व मधु शर्मा ने कहा कि मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल में यूनियन की महासचिव शकुन्तला व अन्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, खींचातानी व मारपीट की गई। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मंत्री यूनियन की बातचीत सुनने की बजाय तानाशाही तरीका अपनाकर आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरोज, रीना, ओ.पी. माटा, जगपाल राणा, नीलम, रूपा राणा, मधु शर्मा व सन्तोष ने वर्करों को संबोधित किया।